प्रकाशन का 46 वां वर्ष
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई–पेपर
www.facebook.com/shailsamachar
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक–28 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 19–26 जुलाई 2021 मूल्य पांच रूपए

# क्या भ्रष्टाचार की फर्जी शिकायत पर आईपीसी की धारा 505(2) के तहत मामला दर्ज हो सकता है

## प्रवीण गुप्ता की शिकायत से उठा सवाल

**शिमला/शैल।** प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग में कार्यरत अतिरिक्त निदेशक प्रवीण गुप्ता ने शिमला के थाना सदर में एक एफआईआर 20 जुलाई को दर्ज करवाई है। गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि बद्दी – बरोटीवाला – नालागढ़ फार्मा एण्ड ड्रग ऐसोसियेशन की ओर से सोशल मीडिया में एक जाली और मनघडंत पत्र वायरल हो रहा है। गुप्ता ने दावा किया है कि उक्त ऐसोसियेशन की ओर से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है क्योंकि उन्होंने इस बारे में इन्कार किया है। प्रवीण गुप्ता ने आरोप लगाया है कि इस पत्र में उनके और उनके परिवार के सदस्यों को घटिया झूठे और आधारहीन आरोप लगाकर उन्हे परिवार सहित बदनाम करने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने गुप्ता की इस शिकायत पर आई पीसी की धाराओं 505(2) 500 और 504 में एफआईआर दर्ज करके इस मामले की छानबीन एसएचओ संदीप चौधरी को सौंपी गयी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिकायत का आधार बने पत्र में भ्रष्टाचार और सरकार के संरक्षण तथा कई अन्य आरोप भी हैं।

प्रवीण गुप्ता इस समय पर्यावरण विभाग में अतिरिक्त निदेशक प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड में अधीक्षण अभियन्ता और पर्यावरण इम्पैक्ट असैसमैन्ट अप्रेज़ल विशेषज्ञ कमेटी के सदस्य सचिव की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अभी पिछले दिनों प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में मुख्य अभियन्ताओं के भी दो पद सृजित किये गये है। माना जा रहा है कि शीघ्र ही बोर्ड में इस पद पर भी उनकी पदोन्नति हो जायेगी। स्मरणीय है कि जब 2016 में Preservation of Kasauli and its Environs ने एनजीटी में एक याचिका दायर की थी उसमें जब प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी पेश हुए थे तो उनकी भूमिका पर एनजीटी ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी। उनजीटी के समक्ष पेश हुए अधिकारियों में यह प्रवीण गुप्ता भी शामिल थे। एनजीटी की टिप्पणीयों पर आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की है।

अब जब प्रवीण गुप्ता ने थाना सदर में एफआईआर दर्ज करवायी है और उस पर पुलिस ने जो धाराएं लगाई है उससे अनचाहे ही एक नयी चर्चा छिड़ गयी है। कानून के जानकारों के मुताबिक आईपीसी की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वह शायद इसमें बनती ही नहीं है। क्योंकि यह मामला धारा 505 (2), 500 और 504 के तहत दर्ज किया गया है। इसमें धारा 500 और 504 दोनो संज्ञेय नही है। यह शैडयूल के मुताबिक Non Cognizable धाराएं हैं। इनमें Defamation का मामला सीधा अदालत में दायर होता है। धारा 505(2) उन मामलों में आकर्षित होती है जहां पर किसी लिखित, प्रकाशित या मौखिक ब्यान–कथन से दो वर्गो/समुदायों के बीच शत्रुता आदि बढ़ने की संभावना हो वहां यह धारा आकर्षित होती है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या प्रवीण गुप्ता पर लगाये आरोपों से दो समुदायों के बीच विभिन्न वर्गो के बीच घृणा, शत्रुता या दुर्भावना पैदा हो सकती है। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ बेबुनियाद और फर्जी शिकायत में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हो तो क्या उससे सामाजिक सदभाव बिगड़ने की आशंका हो सकती है?

यदि पुलिस को प्रवीण गुप्ता की शिकायत पर सामाजिक सदभाव बिगड़ने की संभावना नज़र आयी है तो उससे तो यह स्वत: ही प्रमाणित हो जाता है कि गुप्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है। तब इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सीधे सामने आकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का साहस कैसे करेगा? क्या तब कोई गुमनाम या फर्जी शिकायत कर्ता होने का ही रास्ता नहीं लेगा? पुलिस द्वारा इसमें यह एक धारा 505(2) लगाये जाने से सारे मामले की गंभीरता ही बदल जाती है। पुलिस इस मामले की जांच कैसे आगे बढ़ाती है और अदालत क्या संज्ञान लेती है यह देखना रोचक होगा। वैसे गुप्ता द्वारा दी गयी शिकायत में यह खुलासा नहीं किया गया है कि यह फर्जी पत्र उनके पास या इस ऐसोसियेशन के पास किस माध्यम से आया है। कानून के जानकारों के मुताबिक इस शिकायत की जांच और उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे तथा कईयों पर इसके छीटें पड़ेंगे क्योंकि अब यह मामला सार्वजनिक विषय बन गया है।

## यह है दर्ज हुई एफआईआर

1:- Case FIR No. 143/21 Dated 20.07.2021 u/s 505(2),500,504 IPC has been registered at PS Sadar on the complaint of Sh. Parveen Gupta Additional Director, Department of Environment, Science and Technology, Paryavaran Bhawan, Near US Club, Shimla that one forged, fabricated letter has been circulated on behalf of the Baddi Barotiwala Nalagarh Parma and Drug association whereby certain derogatory, false, baseless and wild allegations have been leveled against him and his family. This letter has not been issued by and on behalf of the Baddi Barotiwala Nalagarh Parma and Drug association as denied by them. This letter has been issued by some vested interest persons, tarnishing him and his family image. Insp/ SHO Sandeep Choudhary PS Sadar is investigating the case

## यह हैं आईपीसी की धाराएं

Section 505. Statements conducing to public mischief.
1[505. Statements conducing to public mischief.-- 2[(1)] Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumour or report,
(a) with intent to cause, or which is likely to cause, any officer, soldier, 3 [sailor or airman] in the Army, 4 [Navy or Air Force] 5 [of India] to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such; or
(b) with intent to cause, or which is likely to cause, fear or alarm to the public, or to any section of the public whereby any person may be induced to commit an offence against the State or against the public tranquility; or
(c) with intent to incite, or which is likely to incite, any class or community of persons to commit any offence against any other class or community, shall be punished with imprisonment which may extend to 6[three years], or with fine, or with both.
7[(2) Statements creating or promoting enmity, hatred or ill-will between classes. Whoever makes, publishes or circulates any statement or report containing rumour or alarming news with intent to create or promote, or which is likely to create or promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, feelings of enmity, hatred or illwill between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.
(3) Offence under sub-section (2) committed in place of worship, etc. Whoever commits an offence specified in sub-section (2) in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.]
Exception. It does not amount to an offence, within the meaning of this section, when the person making, publishing or circulating any such statement, rumour or report, has reasonable grounds for believing that such statement, rumour or report is true and makes, publishes or circulates it 2 [in good faith and] without any such intent as aforesaid.]

# राज्यपाल ने की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 52वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता

**शिमला/शैल।** राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है, हर व्यक्ति जीवनभर शिक्षा प्राप्त करता है लेकिन यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। शिक्षा देने वाले और शिक्षा ग्रहण करने वाले दोनों को यह पता होना चाहिए कि वह क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारी उच्च परम्पराओं से इसे कैसे जोड़ें और कौन-कौन से विषय होने चाहिए, इस पर कार्य किया जाना चाहिए।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम युवा पीढ़ी को क्या विचार दे रहे हैं। यह आवश्यक है कि उनमें सामाजिक और राष्ट्र हित के विचार जागृत किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को आघात पहुंचाने के लिए आक्रांताओं ने हमारी शिक्षा प्रणाली को समय-समय पर निशाना बनाया।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का वैभवपूर्ण और प्रगतिशील इतिहास रहा है। 51 वर्ष की लम्बी यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय ने अकादमिक और शोध गतिविधियों में अनेक मील के पत्थर स्थापित किए हैं।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने ज्ञान, विज्ञान, कला और तकनीक के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि इस परम्परा को और सशक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा के लाभ हमारे व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ समाज और देश को समर्पित किए जाने चाहिए।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि बेहतर समाज की स्थापना के लिए सभी को विकास की यात्रा में पीछे रहे लोगों को आगे बढ़ने के लिए संवेदनशीलता के साथ योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी युवा शक्ति को बौद्धिक ज्ञान प्रदान कर रचनात्मक दिशा प्रदान करनी चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हम समसामयिक चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं में योग्यता और साहस विकसित करें, तभी विश्वविद्यालय सही मायनों में अपनी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को शोध का केंद्र बनाया जाना चाहिए जहां शिक्षा का आधार चरित्र निर्माण हो। उन्होंने गुणात्मक शिक्षा के साथ-साथ विश्वविद्यालय के ग्रेड को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध और प्रौद्योगिकी के शिक्षण और सीखने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने उच्चस्तरीय नौकरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ व्यक्तित्व के विकास के जरूरी शिक्षा भी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी यह सुनिश्चित किया है कि विकास निर्बाध गति से चलता रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती को मनाने के लिए राज्य स्तर पर 51 कार्यक्रमों के आयोजन की योजना तैयार की परन्तु महामारी के कारण इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस उपयुक्त तरीके से मनाने के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने विश्वविद्यालय में 150 शिक्षक नियुक्त करने और 12 नए संकाय शुरू करने के लिए भी विश्वविद्यालय की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्रभावी कामकाज के लिए हर संभव मदद प्रदान करेगी।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 6.73 करोड़ रुपये की लागत की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसकी स्थापना पर 20 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने शिक्षक कॉलोनी में 16 लाख रुपये की लागत से निर्मित ट्रांसफॉर्मर हॉल, 36 लाख रुपये की लागत से सौंदर्यीकरण कार्य और पार्किंग, 1.12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मॉडल स्कूल के चौथे चरण, 1.49 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अकादमिक स्टाफ कॉलेज के फैकल्टी हाउस की अतिरिक्त मंजिलों और 49 लाख रुपये की लागत से निर्मित परीक्षा स्टोर और तीन दुकानों, 1.07 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पुस्तकालय भवन 1.49 करोड़ रुपये की लागत से संकाय अतिथि गृह का जीर्णोधार, 35 लाख रुपये की लागत से विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति कार्यालय के सामने सौन्दर्यीकरण कार्य व पार्किंग को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ छात्रों को सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक व्यक्तित्वों ने इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, पीजीआई और एआईआईएमएस के वर्तमान निदेशक तथा अनेक प्रमुख लोग शामिल हैं।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने भी इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है वह विश्वविद्यालय के प्रथम विधि स्नातक है।

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने विश्वविद्यालय के 52वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 51 वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय में आशातीत विकास हुआ है। विश्वविद्यालय में 13 संकाय, 9 परिसर और 47 विभाग तथा 18 विशेष अध्ययन केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय में 13 पीठ स्थापित किए गए हैं जिनमें शिक्षण और शोध कार्य किया जा रहा है। यह पीठ हमें राष्ट्र निर्माताओं के सिद्धांतों के बारे में अवगत करवाती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 34 वर्षों के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वित की है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह शिक्षा नीति भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाएगी।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकन्दर कुमार ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तित्वों का स्वागत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की गतिविधियों में विस्तार किया गया है। नए छात्रावास और विभाग खोले गए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग में और सुधार होगा।

विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य, विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य, संस्थापक निदेशक, विभागाध्यक्ष और गैर शिक्षक कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

# प्रदेश के कर्मचारियों से निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आग्रह:जय राम ठाकुर

**शिमला/शैल** राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों की उचित मांगों को समय-समय पर पूरा किया गया है। यह बात मुख्यमंत्री जय

राम ठाकुर ने ऑकओवर में अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर के नेतृत्व में भेंट करने आए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं और प्रदेश सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार के स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर सरकार की नीतियां कार्यान्वित करने का दायित्व होता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों ने प्रदेश में कोविड-19 के प्रभावी प्रबन्धन में अहम भूमिका निभाई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद, राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को देय भत्ते समय-समय पर मिलते रहें। उन्होंने कोरोना महामारी के संकट के दौरान भी राज्य सरकार के साथ खड़े रहने के लिए प्रदेश के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित करेगी ताकि उन्हें सरकार के साथ अपने मुद्दे उठाने का अवसर मिल सके। उन्होंने संघ को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के उचित मुद्दों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निवारण करने का प्रयास करेगी, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहती है।

जय राम ठाकुर ने कर्मचारियों से निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आग्रह किया ताकि हिमाचल प्रदेश को देश का आदर्श राज्य बनाया जा सके। उन्होंने संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित किया जाएगा क्योंकि वे सरकार का अहम हिस्सा है।

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य में सम्पूर्ण एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा उन्हें पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से जेसीसी की बैठक को बुलाने का भी आग्रह किया ताकि कर्मचारी अपने विभिन्न मुद्दे एवं मांगें सरकार के समक्ष रख सकें।

संघ के महासचिव राजेश शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। करसोग के विधायक हीरा लाल तथा संघ के अन्य नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रीना
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

# राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई

**शिमला/शैल।** राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर मुस्लिम भाई-बहनों को देश में मनाई जा रही ईद-उल-जुहा के शुभ अवसर पर बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संदेश में सभी मुस्लिम भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके खुशहाल एवं समृद्ध जीवन की कामना की। उन्होंने सभी के लिए खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद-उल-जुहा सर्वोच्च बलिदान की भावना का प्रतीक है और यह त्यौहार समाज में शांति, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से राज्य की प्रगति, समृद्धि और शांति के लिए मिल-जुलकर कार्य करने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि ईद-उल-जुहा ईश्वर के प्रति त्याग और निष्ठा का त्यौहार है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार प्रेम और भाईचारे के बंधन को अधिक मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री ने त्यौहार मनाने के दौरान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासियों से कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे सामाजिक दूरी के नियमों का पालन और मास्क पहनना सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

**HIMACHAL PRADESH**
**PUBLIC WORKS DEPARTMENT**
**e-Procurement Notice**
**INVITATION FOR BIDS (IFB)**

1.The **Executive Engineer HPPWD Kotkhai Distt Shimla H.P** on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

| Sr.No. Name of Work | Estimated Cost | EMD | Cost of Tender | Time | Eligible Class of Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Improvement of Kharapather Chaindal Shilaroo Road in K.M. 0/00 to 4/500 under SCCP (SH:- C/o, B/Wall at R.D. 2/040 to 2/065, 2/075 to 2/082.50, 2/720 to 2/745 and 3/340 to 3/365 and R/Wall at R.D. 3/345 to 3/357.50) | Rs.9,89,226/- | Rs.19,800/- | Rs.350/- | Two Month | Class D And Class C |
| 2. Improvement of Jalath-I to Jalath-II Road in K.M. 0/00 to 3/00 (SH:- C/o, R/Wall in PCC at R.D. 2/312.75 to 2/322.75) | Rs.6,11,481/- | Rs.12,500/- | Rs.350/- | Two Month | Class D And Class C |

**Tender document and other instructions can be downloaded or viewed online from the portal https://hptenders.gov.in by the firm/individual registered on the website which is free of cost.**
**Key Dates:**

| | |
|---|---|
| 1. Date of Online Publication | 04-08-2021 11:00 HRS |
| 2. Document Download Start and End Date | 04-08-2021 1130 HRS upto 12-08-2021 1730 HRS |
| 3. Bid Submission Start and End Date | 04-08-2021 1130 HRS upto 12-08-2021 1800 HRS |
| 4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document | 13-08-2021 upto 1030 HRS |
| 5. Date of Technical Bid opening, | 13-08-2021 1100 HRS |
| 6. Evaluation of Technical Bid followed by Opening of Financial Bid. | Date to be announced |

**Adv. No. 2733/21-22** **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

# 2 अगस्त से 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में 2 अगस्त, 2021 से सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हुए स्कूल खोलने को अनुमति प्रदान की गई।

इन कक्षाओं के लिए आवासीय

और आंशिक आवासीय विद्यालय भी सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। विश्वविद्यालयों के शोध विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तिथियों से विश्वविद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने 5वीं और 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाई संबंधी किसी संशय के निवारण के लिए 2 अगस्त, 2021 से स्कूल आने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षण संस्थानों को इस वर्ष 26 जुलाई से मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए जिला कुल्लू के निरमण्ड और जिला शिमला के कोटखाई एवं जुब्बल में तीन उपमण्डल कार्यालय (नागरिक) खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिला के विकास खण्ड पांवटा साहिब के पुनर्गठन से तिरलोधार में नया विकास खण्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। मंडी जिला के सुन्दरनगर व बल्ह विकास खण्डों के पुनर्गठन से धनोटू के शेगली में नया विकास खण्ड बनाने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती द्वारा जे.ओए. (आईटी) के 100 पद भरने का निर्णय लिया।

शिमला जिला के कोटखाई स्थित कलबोग में नई उप-तहसील और जुब्बल-कोटखाई के टिक्कर में अग्निशमन केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है।

बैठक में मैसर्ज प्रीमियर अल्कोबेव प्राईवेट लिमिटिड कांगड़ा जिला के संसारपुर टेरेस में 250 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता से इथेनोल संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमति पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल में मरीजों की सुविधा के लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, हमीरपुर में 4.28 करोड़ रुपये की लागत से सीटी स्कैन-128 स्लाइस मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के भराड़ी में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सह-शैक्षणिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और सर्वेयर तथा ऑफिस असिस्टेंट-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर के दो ट्रेड्स को सीटों सहित मोटर वाहन मैकेनिक एवं फिटर में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। यह संस्थान निजी भवन में चल रहा है इसलिए परिवर्तित किए गए ट्रेड्स को संस्थान को अपने भवन में स्थानांतरित करने के पश्चात् आरम्भ किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में नए स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़-जमूला के सुचारू संचालन के लिए तीन अतिरिक्त पद भरने की मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में चालकों के तीन पदों को दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरने का निर्णय लिया।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में चैकीदार के 5 पद दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ का नाम बदलकर शहीद सुबेदार संजीव कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ रखने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। शहीद सुबेदार संजीव कुमार को उनकी वीरता एवं साहस के लिए मरणोपरांत शहीद सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था।

राज्य में कोविड-19 की स्थिति, कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों और शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम, यूजीसी के दिशा-निर्देशों व शिक्षा संस्थानों को खोलने पर भी मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुति दी गई।

# मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत प्रदेश में 358 करोड़ रुपये की 2057 इकाइयां स्थापित:बिक्रम सिंह

**शिमला/शैल।** प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्योगपतियों एवं उद्यमियों को प्रदेश सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा ऐसे लोगों को प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। यह बात उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्योग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस के क्षेत्र में देश में 7वें स्थान पर है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के लिए रेडियो, प्रिंट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लैंड बैंक बनाया गया है, जिसके तहत 17,765 बीघा भूमि उपलब्ध है। इसके अलावा लगभग 5000 बीघा भूमि वन स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात् उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के तहत दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए अब तक 7367 करोड़ रुपये के निवेश के 138 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरिंग एजेंसी द्वारा 1236 करोड़ रुपये के निवेश की 80 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिससे 3814 लोगों को रोजगार मिला। बिक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत प्रदेश में 358 करोड़ रुपये के निवेश की 2057 इकाईयां स्थापित की गईं। योजना के तहत 131.11 करोड़ रुपये का उपदान प्रदान किया गया है तथा 6305 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री स्टार्ट अप योजना के अंतर्गत 8 स्टार्ट अप को दो करोड़ रुपये की सीड फंडिंग के लिए स्वीकृति प्रदान की है। योजना के तहत 32 स्टार्ट अप को इन्क्यूबेशन सेंटर से स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत प्रत्येक स्टार्ट अप को 25 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिला ऊना में लगभग 100 करोड़ रुपये के निवेश से मैगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रोफूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजिज योजना को प्रदेश में भी कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश में पांच वर्षों में 54.57 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर भी बल दिया जाएगा।

उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग राम सुभग सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों आदि द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जैम) के माध्यम से वस्तुओं व सेवाओं का प्रापन किया जा रहा है। जैम पोर्टल पर 2562 उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इस पोर्टल पर प्रदेश के 10,780 विक्रेता पंजीकृत हैं। प्रदेश सरकार के विभिन्न 1492 कर्मचारियों व अधिकारियों तथा 280 स्थानीय कंपनियों को जैम से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों आदि द्वारा 357 करोड़ रुपये की वस्तुओं व सेवाओं का प्रापन किया गया है।

निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा उद्योग मंत्री को आश्वस्त किया कि विभाग प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत निरंतर प्रयास करते हुए उद्योग क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

# हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक की प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अपील

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय से 20 जुलाई को जारी प्रैस विज्ञप्ति में प्रदेश के लोगों व पर्यटकों को बरसात के मौसम से अगाह किया है। प्रदेश में हो रही भारी बरसात के चलते अगले कुछ दिनों तक आंधी, तूफान व लगातार बरसात होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में प्रदेश भर में, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में लहासे गिरने, सड़क टूटने/बह जाने और नदी नालों में भारी बाढ़ जैसी स्थिति अचानक उत्पन्न हो सकती है। जिस कारण सफर करना जोखिम भरा व घातक हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुन्डू प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अपील करते हैं कि ऐसे मौसम में केवल उन स्थितियों में ही घर से बाहर निकले जब ऐसा करना अत्यंत आवश्यक हो तथा यदि सफर करना अत्यंत आवश्यक भी हो तो अपने वाहन के सामने देखने वाले शीशे की अच्छी तरह सफाई करें और वाहन को अत्यन्त सावधानी से चलाएं। क्षेत्र में धुन्ध होने के कारण विजीबिलटी कम होने पर वाहन नियत्रित गति में ही चलाएं। साथ ही ऐसे मौसम में उन क्षेत्रों में न जाएं जहां पर अकसर भूमि कटाव/लहासे गिरना, बाढ़ व बादल फटने जैसी दुर्घटनाएं आम तौर पर घटित होती हैं।

हिमाचल प्रदेश में अधिकतर क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण बरसात के मौसम में बहुत सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें से अधिकतर जानलेवा व घातक साबित होती हैं इसलिए उपरोक्त सुझावों का विशेष ध्यान रखकर पालन करें तथा अपने आप और अपने परिवार जनों को सुरक्षित रखने में सहयोग दें।

# राज्य में अब तक 2,00,704 कोरोना संक्रमित लोगों को बचाया जा चुका है

**शिमला/शैल।** राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं, उचित देखभाल व उपचार के परिणामस्वरूप कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों के जीवन को बचाने में राज्य सरकार काफी हद तक सफल रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण अब तक राज्य में 2,00,704 (दो लाख 704) संक्रमित लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 महामारी के खिलाफ अब तक 27,53,890 लोगों के टेस्ट किए गए है, जिनमें से 25,48,778 लोग नेगेटिव पाए गए है। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 2,05,061 लोग कोविड-19 संक्रमित पाए गए है, जिनमें से अब तक 2,00,704 लोग स्वस्थ हो चुके है और राज्य में अब कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या केवल मात्र 841 रह गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 महामारी का प्रभाव कम हुआ है लेकिन यह महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभी भी इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचाव के दृष्टिगत कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे परस्पर दूरी बनाए रखना, साबुन-पानी से हाथ धोना और मास्क का उपयोग करना आदि नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

# ट्रैफिक जाम को लेकर प्रदेश सरकार का भ्रामक सूचना से बचने का आग्रह

**शिमला/शैल।** प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश में भारी ट्रैफिक जाम और भारी मात्रा में पर्यटकों द्वारा राज्य से बाहर जाने के संबंध में एक भ्रामक वीडियो वायरल हुई है।

प्रवक्ता ने बताया कि यह वीडियो भ्रामक और तथ्यों के विपरीत है तथा यह वीडियो हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कें खुली हैं और प्रदेश के किसी भी भाग में इस प्रकार की ट्रैफिक जाम जैसी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों का स्वागत है और सरकार पर्यटकों से कोविड अनुकूल व्यवहार का उचित तरीके से पालन करने का आग्रह करती है।

उन्होंने पर्यटकों से जलाशयों विशेषकर तेज प्रवाह वाली नदियों और नालों के निकट न जाने और पहाड़ों में सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने का आग्रह किया। उन्होंने पर्यटकों से पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाने को कहा।

# नौणी विश्वविद्यालय ने विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा

**शिमला/शैल।** डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों के लिए प्रोविजिनल रूप से भर्ती उम्मीदवारों के लिए लिखित आब्जेक्टिव टाइप परीक्षा की तारीक की अधिसूचना जारी कर दी है।

परीक्षा की तिथियां इस प्रकार हैं ड्राइवर (पोस्ट कोड 212) और फार्मासिस्ट (पोस्ट कोड 302) के लिए परीक्षा की तिथियां क्रमशः 15 सितंबर और 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी। प्रयोगशाला तकनीशियन (पोस्ट कोड 303) और जूनियर इंजीनियर सिविल (पोस्ट कोड 204) के लिए परीक्षा क्रमशः 22 सितंबर और 3 अक्तूबर को होगी जबकि फील्ड असिस्टेंट (पोस्ट कोड 208) के पद के लिए परीक्षा 17 अक्तूबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 के बीच आयोजित की जाएगी।

पात्र उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर/संशोधित प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.yspuniversity.ac.in से डाउनलोड करना होगा जो परीक्षा से 10 दिन पहले उपलब्ध होगा। उम्मीदवार 01792-252444 या rectt.uhf@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

## आत्मसम्मान के हनन से विकास का विनाश हो जाता है

......चाणक्य

### सम्पादकीय

# सच से क्यों भाग रही है मोदी सरकार

जब सरकार ही सच का सामना करने का साहस न कर पाये जो सामने दिवार पर साफ–साफ लिखा है उस पर ऑखे बन्द कर ले और यह सब लोकतान्त्रिक सरकार में हो जाये तो क्या लोकतन्त्र को बचाया रखा जा सकेगा? आज यह सवाल हर संवेदलशील बुद्धिजीवी के लिये एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है क्योंकि आज सरकार यह कह रही है कि इस कोरोना में आक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रदेश से ऐसी कोई जानकारी कोई आंकड़ा उसके पास आया ही नहीं है। आक्सीजन के लिये किस तरह का हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ था यह पूरा देश जानता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केन्द्र की मोदी सरकार किस तरह आक्सीजन के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गये थे यह पूरा देश जानता है बल्कि देश के लगभग सभी उच्च न्यायालयों ने इस संकट का संज्ञान लेकर सरकारों से सवाल पूछे हैं और समय- समय पर रिपोर्टे तलब की हैं यह सब रिकार्ड उपलब्ध है। जब राज्य सरकारें इस संकट से जूझ रही थी और आक्सीजन की सप्लाई केन्द्र से हो रही थी क्या तब केन्द्र सरकार का राज्यों से यह जानना फर्ज नहीं था कि कहीं आक्सीजन की कमी से कोई मौतें तो नहीं हो रही है। आज जब केन्द्र सरकार यह कह रही है कि राज्यों ने ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं भेजी है तब क्या केन्द्र को राज्यों से यह पूछना–जानना नहीं चाहिये था। क्या आज राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर उनको लोगों का दर्द कम किया जा सकता है जिन्होंने आक्सीजन के कारण अपनों को खोया हैं क्या केन्द्र सरकार का यह इन्कार उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं हो जायेगा? इस समय मौत के आंकड़ो को लेकर केन्द्र और अन्य ऐजेन्सीयों के आंकड़ों में जो अन्तर सामने आ रहा है उससे सरकार की विश्वसनीयता पर और गंभीर प्रश्नचिन्ह लगते जा रहे हैं। क्योंकि सरकार का आंकड़ा अभी चार लाख बीस हजार तक ही पहुंचा है जबकि अन्यों के मुताबिक यह आंकड़ा चालीस लाख से अधिक है। इन अन्यों में एक अध्ययन करने वाले इसी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार रहे हैं। कोरोना के प्रबन्धन में सरकारों की असफलता झेल रहे आम आदमी के सामने जब मौतों पर भी सरकार का इन्कार सामने आया है तब उसकी हालात क्या हो रही होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि जब मौतों को भी सरकार राजनीति का विषय बना दे तो ऐसी सरकार का केवल मतदान के दिन ही सच से सामना करवाया जा सकता है।

इसी तरह जासूसी प्रकरण में भी सरकार अपनी भूमिका से इन्कार कर रही है। सरकार और भाजपा का हर नेता केन्द्र से लेकर राज्यों तक सरकार का पक्ष रखते हुए इस प्रकरण को बाहरी ताकतों की साजिश करार दे रहा है। इस प्रकरण मे जो अब तक खुलासे सामने आये हैं उनके मुताबिक इसमें पत्रकारों, राजनेताओं, सरकारी अधिकारियो, उद्योगपतियों और न्यायपालिका तक के फोनटैप हुए हैं। इन लोगों की जासूसी की गयी है। इस जासूसी के लिये इजरायल की एक कम्पनी एनओएस का पैगासस स्वाईवेय इस्तेमाल हुआ है। मोदी सरकार के दो मन्त्रीयों की भी जासूसी हुई है। सरकार यह जासूसी होने से इन्कार नहीं कर रही है केवल यह कह रही है कि इसमें उसका हाथ नहीं है। भाजपा नेता पूर्व मन्त्री ड़ा स्वामी ने यह कहा है कि जासूसी करने वाली कंपनी एनओएस पैसे लेकर जासूसी करती है। इजरायल का कहना है कि यह स्पाईवेयर केवल सरकारों को ही बेचा जाता है। भारत सरकार इसे देश के खिलाफ विदेशी ताकतों की साजिश करार दे रही है। ऐसे में क्या यह सवाल उठना स्वभाविक नहीं हो जाता कि जब कोई बाहरी ताकत देश के खिलाफ ऐसा षडयन्त्र कर रही है तो भारत सरकार को तुरन्त प्रभाव से इसकी जांच करनी चाहिये। लेकिन मोदी सरकार यह जांच नहीं करवाना चाहती। जब सरकार ने यह जासूसी नहीं करवाई है तो वह जांच करवाने से क्यों भाग रही है। जासूसी हुई है इससे सरकार इन्कार नहीं कर रही है। सरकार ने की नहीं है। तब क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन जाती है कि इस प्रकरण की जांच करे। सरकार का जांच से भागना देश और सरकार दोनों के ही हित में नहीं होगा।

आक्सीजन की कमी से हुई मौतों से इन्कार करना और इतने बड़े जासूसी प्रकरण के घट जाने पर जांच से भागना ऐसे मुद्दे आज देश के सामने आ खड़े हुए हैं जिन पर हर आदमी को अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सामने रख कर विचार करना होगा और अपने बच्चों के भविष्य को सामने रखकर विचार करना होगा। क्योंकि ऐसे ही इन्कारों का परिणाम है मंहगाई और बेरोज़गारी।

# अफगानिस्तान में सौफ्ट डिप्लोमेसी यहां बड़ा हथियार साबित होगा, सैन्य हस्तक्षेप से बचे भारत

**गौतम चौधरी**

अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी और तालिबानी प्रभाव में विस्तार को लेकर भारत खासा चिंतित दिख रहा है। दिन व दिन अफगानिस्तान की स्थिति खराब होती जा रही है। समाचार माध्यमों में आ रही खबरों से यही लग रहा है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब होते जा रहे हैं। कुल 421 जिलों में से 150 जिलों में अफगानिस्तानी सैनिकों के साथ तालिबानी लड़ाके जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुततबिक तालिबान अफगानी सैनिकों पर भाड़ी पड़ रहे हैं और वे आगे गढ़ रहे हैं। बहुत सारे जिले तालिबानियों के कब्जे में चले गए हैं। पिछले कुछ ही दिनों पांच हजार से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। देश के अंदर ही दो लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं।

ऐसे में भारत को अब यह डर सताने लगा है कि उसके द्वारा किए गए निवेश का क्या होगा? हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान में अपने वाणिज्यिक दूतावास से अपने राजनायिकों और स्टाफ को वापस बुला लिया है। तालिबान के खात्मे के बाद पिछले करीब 20 सालों से अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हो गए थे। बता दें कि अफगानिस्तान इस क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। ये शायद एकमात्र सार्क राष्ट्र भी है, जिसके लोगों को भारत से खासा लगाव है। पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में बड़ा निवेश किया है। भारत ने यहां महत्वपूर्ण सड़कों, बांधों, बिजली लाइनों और सबस्टेशनों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण किया है। भारत की विकास सहायता 3 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

साल 2011 के भारत–अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौते ने यहां बुनियादी ढांचे और संस्थानों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सिफारिश की थी। लिहाजा कई क्षेत्रों में अफगानिस्तान में निवेश को बढ़ावा दिया गया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब एक अरब डॉलर का है। नवंबर 2020 में जिनेवा में अफगानिस्तान सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि अफगानिस्तान का कोइ भी हिस्सा आज भारत के प्रोजेक्ट से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा था कि यहां के 34 प्रांतों में 400 से अधिक प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन अब इन सारे प्रोजेक्ट का भविष्य अधर में लटक गया है।

हालांकि अफगानिस्तान में आज जिस परिस्थिति का सामना भारत को करना पड़ रहा है वह कोई अप्रत्याशित नहीं है। आज नहीं तो कल नाटो सैनिकों की वापसी तय थी। अमेरिका व्यापारिक मनोवृति का देश है। जहां उसके आर्थिक हित नहीं सधते वहां वह रूक ही नहीं सकता है। विश्व व्यापार केंद्र पर हमले के बाद अमेरिका ने इस्लामिक दुनिया के दो ठिकानों पर हमला किया। पहला इराक और दूसरा अफगानिस्तान। इराकी हमले के बाद सद्दाम हुसैन का खात्मा हुआ और उसकी परिणति अल बगदादी एवं उसके संगठन आईएसआईएस के रूप में हुई। अंत में यह लड़ाई सीरिया पहुंच गयी और रूसी सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिका को वहां से पीछे हटना पड़ा।

अमेरिका का दूसरा मोर्चा, अफगानिस्तान में था। अब वियतनाम की तरह अमेरिका को यहां से भी वापिस जाना पड़ रहा है। जिस तालिबान को अमेरिका, पाकिस्तान और सउदी अरब ने मिलकर खड़ा किया था वही तालिबान इन तीनों देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है और आज भी इन तीनों के लिए तालिबान खतरनाक साबित हो रहा है।

अफगानिस्तान में भारत की भूमिका थोड़ी भिन्न है। अफगानिस्तान में भारत सदा से सैन्य हस्तक्षेप से बचता रहा है। भारत, अफगानिस्तान में सौफ्ट डिप्लोमेसी को ही अपना हथियार बनाया है। अंततोगत्वा इसका लाभ भारत को मिलना चाहिए। अफगानिस्तान में यदि भारत की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है तो उसके लिए भारत की आंतरिक राजनीति जिम्मेदार है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली हार्डकोर हिन्दुवादी सोच की सरकार का असर अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। वर्तमान तालिबानी कमांडरों में से ऐसे कई कमांडर ऐसे हैं, जिसकी धार्मिक और भौतिक, दोनों प्रकार की शिक्षा भारत में हुई है। उन कमांडरों को अपने पक्ष में किया जा सकता था लेकिन संभवतः वर्तमान सरकार ने उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया और उसका प्रतिफल हमारे सामने है।

दूसरा अंतर्विरोध अमेरिका को लेकर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक भारत महाशक्तियों के गुटों से अपने आप को अलग दिखाता रहा है। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने इस विदेश नीति में संशोधन कर दिया और अमेरिका के प्रति अपना झुकाव सार्वजनिक कर दिया। वर्तमान विश्व का अधिकतर इस्लामिक देश अमेरिका के खिलाफ है। तालिबान भी अमेरिका के खिलाफ है। ऐसे समय में अमेरिकी खेमा में जाना, भारत की कूटनीतिक अदूरदर्शिता को परिलक्षित करता है। इसके कारण भारत को कई स्थानों पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में और परेशानी होने वाली है। अफगानिस्तान में भारत के प्रति जो तालिबान का आक्रोश दिख रहा है उसके लिए अमेरिका परस्ती भी एक बड़ा कारण है।

अब अफगानिस्तान में भारत को क्या करना चाहिए? अफगानिस्तान में भारत को अपने आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा करनी है, तो विकासात्मक कार्य के साथ ही साथ सैन्य हस्तक्षेप से बचना होगा। रूस के साथ अपने संबंधों को सुधारना होगा और पाकिस्तान के साथ लचीला रवैया अपनाना होगा। हालांकी अफगानिस्तान में अब तुर्की भी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है लेकिन भारत को उस ओर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान के लिए भारत की सौफ्ट पॉलीसी ही सबसे अधिक कारगर साबित होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ अन्य प्रभावशाली ताकतों को भी अपने पक्ष में करना भारत के लिए हितकर साबित होगा। खैर अभी अफगानिस्तान के हालात पूर्ण रूप से अनियंत्रित नहीं हुए हैं और बहुत खेल होना वहां बाकी है लेकिन भारत को अपनी आंतरिक राजनीति में भी थोड़े परिवर्तन की जरूरत है, जो इस्लामिक दुनिया में हमारी स्थिति को कमजोर कर रहा है। साथ ही अमेरिका परस्ती पर भी हमारे रणनीतिकारों को समीक्षा करनी चाहिए।

# नल से जल की आपूर्ति 66 प्रतिशत स्कूलों और 60 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंची

**शिमला।** कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं (आवासीय स्कूलों) में बच्चों को उनकी भलाई और बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्तूबर, 2020 को कल्पना की गई थी, इन संस्थानों में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के शुरू होने के बाद से दस महीने से भी कम समय में 6.85 लाख (66 प्रतिशत) स्कूलों, 6.80 लाख (60प्रतिशत) आंगनबाड़ी केंद्रों, 2.36 लाख (69प्रतिशत) ग्राम पंचायतों तथा पूरे देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

कोविड-19 महामारी तथा लाकडाउन के कारण बार-बार के व्यवधान के बावजूद आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और केंद्र शासित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सभी स्कूलों, आश्रमशालाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। एक बार स्कूल और आश्रमशालाएं खुलने के बाद बच्चों को सुरक्षित नल का पानी उनके बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर स्वच्छता और बेहतर स्वच्छता में काफी योगदान देगा।

बच्चों को सुरक्षित नल का जल सुनिश्चित करने के लिए 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र तक प्राथमिकता के आधार पर नल के पानी का कनेक्शन पहुंचाएं। प्रधानमंत्री के विजन को साकार के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 2 अक्तूबर, 2020 को देश भर में बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता और तात्कालिकता की भावना लाने के लिए 100 दिनों का अभियान लान्च किया गया था। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान की अवधि के दौरान सभी स्कूलों, आश्रमशालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों और स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्रों में सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सभाएं बुलाई जाएं और प्रस्ताव पारित किए जाएं।

इस अभियान के फलस्वरूप 10 महीने से भी कम समय में 6.85 लाख स्कूल, 6.80 लाख आंगनबाड़ी केंद्र और 2.36 लाख जीपीएस/ सीएचसी में पेयजल और मध्याह्न भोजन पकाने के लिए नल से जल की आपूर्ति होती है, 6.18 लाख स्कूलों के शौचालयों में नल का पानी है और 7.52 लाख स्कूलों में नल के पानी से हाथ धोने की सुविधा है। नल जल आपूर्ति की यह व्यवस्था न केवल बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में योगदान देती है बल्कि जल जनित रोगों को फैलने से भी रोकती है। पानी की उपलब्धता और उपयोग किए गए पानी का शोधन सुनिश्चित करने के लिए 91.9 हजार स्कूलों मे वर्षा जल संचयन और 1.05 लाख स्कूलों में धूसर जल प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। इससे न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि बच्चों में जागरूकता भी पैदा होगी और वे अपनी बढ़ती उम्र में जल प्रबंधन के बारे में सीखने के लिए

प्रेरित होंगे।

असुरक्षित पानी, खराब साफ-सफाई और स्वच्छता के कारण बच्चों को डायरिया, पेचिश, हैजा, टाइफाइड आदि जलजनित बीमारियों की संभावना बनी रहती है। बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में असुरक्षित पानी के सेवन और खराब स्वच्छता के कारण बार-बार संक्रमण होने से स्वास्थ्य पर स्टंटिंग जैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। जिन क्षेत्रों में जल स्रोत आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातुओं आदि से दूषित होते हैं वहां दूषित पानी के लंबे समय तक सेवन से स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए इस अभियान के अंतर्गत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने तथा मध्याह्न भोजन पकाने, शौचालयों/मूत्रालयों में हाथ धोने के लिए निर्धारित गुणवत्ता की नल जल आपूर्ति की जा रही है।

बच्चों, शिक्षकों, सहायक कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और देखभाल करने वाले लोगों को बार-बार हाथ धोने के लिए पाइप से पीने योग्य पानी की जरूरत को स्वीकार करते हुए मिशन सभी स्कूलों, आश्रमशालाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द से जल्द सुरक्षित पाइप जलापूर्ति प्रदान करने पर बल दे रहा है।

15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन लान्च किए जाने के समय देश के 18.98 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17प्रतिशत) नल के पानी के कनेक्शन थे। कोविड-19 महामारी और लाकडाउन के कारण व्यवधान के बावजूद जल जीवन मिशन ने पिछले 23 महीनों में 4.57 करोड़ नल जल कनेक्शन प्रदान किए। फलस्वरूप आज 7.80 करोड़ (41. 14प्रतिशत) परिवारों में नल के पानी की आपूर्ति होती है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत घरेलू कनेक्शन हासिल किया है और 'हर घर जल' बन गया है।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के प्रधानमंत्री के विजन के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए मिशन का आदर्श वाक्य यह है कि 'कोई भी न छूटे' और गांव के हर घर में नल जल कनेक्शन दिया जाना चाहिए। वर्तमान में74 जिलों और लगभग 1.04 लाख गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है और ये 'हर घर जल' बन गए हैं। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की स्थिति https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx पर उपलब्ध जेजेएम डैशबोर्ड से प्राप्त की जा सकती है।

जल गुणवत्ता नमूना संग्रह, परीक्षण और उपयोगकर्ताओं को परिणाम अपलोड/संचारित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ साझेदारी में एक आनलाइन पोर्टल जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) विकसित की गई है। यदि किसी भी पानी के नमूने की जांच दूषित पाई जाती है तो उपचारात्मक कारवाई प्रारंभ करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आटोमेटेड (स्वचालित) चेतावनी भेजी जाती है। इस पोर्टल पर एक व्यक्ति अपने नमूने का पंजीकरण कर सकता है और पानी के नमूने की जांच कराने के लिए निकटवर्ती प्रयोगशाला चुन सकता है। इस पोर्टल को वेबलिंक:https://neer.icmr.org.in /website/main.php पर एक्सेस किया जा सकता है। 25-07-2021 तक डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल के माध्यम से पानी की गुणवत्ता जांच के लिए लगभग 4.9 लाख नमूने प्राप्त हुए हैं। जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई जलापूर्ति सुविधाओं का संचालन और रखरखाव ग्राम पंचायत और/या इसकी उप समिति यानी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति या पानी समिति द्वारा किया जाएगा।

यूएनओपीएस, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ जैसी विकास एजेंसियां भी मिशन, जल संरक्षण और स्कूलों में हाथ धोने आदि जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने में सहायता कर रही हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से 15 अगस्त 2019 को घोषित जल जीवन मिशन 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्यों/केंद्रों के साथ साझेदारी में लागू कार्यान्वयन किया जा रहा है। मिशन का कुल परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये है।

# राज्य में कुल लक्षित आबादी में से 65 प्रतिशत लोगों को दी जा चुकी है कोविड वैक्सीन की पहली खुराक

**शिमला।** कोविड-19 के खिलाफ चुनौतीपूर्ण लड़ाई में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को प्रभावी तरीके से संचालित किया जा रहा हैं। कोविड-19 के खिलाफ इस वैक्सीनेशन महाअभियान के प्रति लोगों में भारी उत्साह है और लोग इसमें बढ़चढ़कर हिस्सा लेकर अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए आगे आ रहे है। जिसके फलस्वरूप यह पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश कोविड महामारी को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा है।

राज्य सरकार के प्रयासों व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान से प्रदेश में अब तक टीकाकरण के लिए लक्षित कुल आबादी में से कुल 65 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 55 लाख 23 हजार पात्र लोग है, जिनका कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण किया जाना है। प्रदेश में संचालित किए जा रहे टीकाकरण महाभियान के अन्तर्गत अब तक राज्य में 35,64,834 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए प्रभावी रणनीति बना कर पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ-साथ ही टीके की पहली खुराक लगा चुके लोगों को कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक भी लगाई जा रही है, जिसके लिए भी सरकार द्वारा प्रभावी रणनीति तैयार कर टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य में 11,48,567 लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक भी लगाई जा चुकी हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत राज्य में अब तक युवा वर्ग टीकाकरण मामले में अग्रिम स्थान पर है। प्रदेश में युवा वर्ग यानी 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 13,80,403 युवाओं का अब तक टीकाकरण कर अभियान के अन्तर्गत पहली खुराक लगाई जा चुकी हैं। 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में 10,98,603 लोगों को, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 7,70,876 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता श्रेणी में 86,669 और अग्रिम पंकित कार्यकर्ता श्रेणी में 2,28,283 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक 23 जुलाई, 2021 तक लगाई जा चुकी है।

लाहौल-स्पीति जिला कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत शत-प्रतिशत आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक लगा कर जहां राज्य का पहला जिला बन चुका है, वहीं प्रदेश के अन्य जिले भी अपने निर्धारित शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है।

# आईआईटी रोपड़ ने अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण-AMLEX विकसित किया

**शिमला।** मेडिकल आक्सीजन सिलेंडरों के कार्यकाल की क्षमता को तीन गुना बढ़ाने के लिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ ने अपनी तरह का पहला ऐसा आक्सीजन राशनिंग उपकरण- AMLEX विकसित किया है जो साँस लेने के दौरान रोगी को आवश्यक मात्रा में आक्सीजन की आपूर्ति करता है और रोगी द्वारा कार्बन डाइआक्साइड ($CO_2$)के बाहर निकालते समय बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया से आक्सीजन की बचत होती है जो अन्यथा अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाती है।

अब तक, साँस छोड़ने के दौरान, आक्सीजन सिलेंडर/पाइप में आक्सीजन उपयोगकर्ता द्वारा उत्सर्जित किए गए कार्बन डाइआक्साइड के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। इससे बड़ी मात्रा में आक्सीजन की बर्बादी होती है। इसके अलावा, मास्क में जीवन रक्षक गैस के निरंतर प्रवाह के कारण आराम की अवधि (साँस लेने और छोड़ने के बीच) में मास्क के खुलने से वातावरण में बड़ी मात्रा में आक्सीजन निकल जाती है। जैसा कि हमने देखा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच मेडिकल आक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई है, यह उपकरण उसी के अवांछित अपव्यय को रोकने में मदद करेगा।

निदेशक, आईआईटी, रोपड़, प्रोफेसर राजीव अहूजा ने कहा कि डिवाइस पोर्टेबल बिजली आपूर्ति (बैटरी) के साथ-साथ लाइन आपूर्ति (220V-50Hz) दोनों पर काम कर सकता है।

इसे संस्था के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के पीएचडी छात्रों- मोहित कुमार, रविंदर कुमार और अमनप्रीत चंदर द्वारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डा आशीष साहनी के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है।

डा साहनी ने बताया कि 'विशेष रूप से आक्सीजन सिलेंडर के लिए बनाया गया, AMLEX को आक्सीजन आपूर्ति लाइन और रोगी द्वारा पहने जाने वाले मास्क के बीच आसानी से जोड़ा जा सकता है। यह एक सेंसर का उपयोग करता है जो किसी भी पर्यावरणीय स्थिति में उपयोगकर्ता के साँस लेने और छोड़ने का सफलतापूर्वक पता लगाता है। यह रेडी टू यूज़ डिवाइस व्यावसायिक रूप से उपलब्ध किसी भी आक्सीजन थेरेपी मास्क के साथ काम करता है जिसमें वायु प्रवाह के लिए कई रास्ते होते हैं।

दयानंद मेडिकल कालेज, लुधियाना में अनुसंधान और विकास के निदेशक डा जीएस वांडर ने नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान महामारी के समय में हम सभी ने जीवन रक्षक आक्सीजन के प्रभावी और उचित उपयोग के महत्व को सीखा है। उन्होंने कहा कि हालांकि कई अस्पताल अपनी आक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरह का उपकरण वास्तव में छोटे ग्रामीण और अर्ध शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में आक्सीजन के उपयोग को सीमित करने में मदद कर सकता है।

प्रो. राजीव अरोड़ा ने कहा कि देश को अब कोविड-19 से निपटने के लिए तेजी से लेकिन सुरक्षित समाधान की जरूरत है। चूंकि वायरस फेफड़ों और बाद में रोगी की श्वास प्रणाली को प्रभावित कर रहा है, इसलिए संस्थान का इरादा डिवाइस के पेटेंट के लिए जाने का नहीं है। उन्होंने कहा कि यह देश के हित में, उपकरण के बड़े पैमाने पर उत्पादन के इच्छुक लोगों को इस तकनीक को मुफ्त में हस्तांतरित करने में आईआईटी को खुशी होगी।

# आज मेरे परिश्रम का फल मिला और मेरा सपना साकार हुआ है: मीराबाई चानू

शिमला। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम सहित कुल 202 किग्रा भार उठाया। मणिपुर की 26 वर्षीय चानू, 2018 में पीठ की चोट के बाद सावधानी से उबरते हुए, देश की पहचान बन गई।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पदक जीतने के साथ ओलंपिक में भारत की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त की और चानू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। खेल मंत्री अनुराग सिह ठाकुर ने मीराबाई चानू को बधाई देते हुए कहा कि आपने देश को गौरवान्वित किया।

रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित फेसबुक लाइव में मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान सुश्री मीराबाई ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि उन्होंने इस दिन के लिए बहुत त्याग किया है और आज उनकी सारी मेहनत का फल मिला और उनका सपना साकार हो गया है।

# जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खाया एक गरीब भारतीय लड़की का झूठा चावल

## यह है मीराबाई चानू की संघर्षमयी कहानी

**इस सत्य घटना को पढ़ने के बाद शब्द ही नही बचे हैं मेरे पास कुछ भी टिप्पणी करने के लिए। बस हज़ार बार नमन कर सकता हूँ इस आदमी जिजीविषा वाली महान मीरा चानू को। पढ़िए उनकी कथा।** (सौ – आर.डी. गुलेरिया)

उस समय उसकी उम्र 10 साल थी। इम्फाल से 200 किमी दूर नोंगपोक काकचिंग गांव में गरीब परिवार में जन्मी और छह भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई चानू अपने से चार साल बड़े भाई सैखोम सांतोम्बा मीतेई के साथ पास की पहाड़ी पर लकड़ी बीनने जाती थी।

एक दिन उसका भाई लकड़ी का गठ्ठर नही उठा पाया, लेकिन मीरा ने उसे आसानी से उठा लिया और वह उसे लगभग 2 किमी दूर अपने घर तक ले आई।

शाम को पड़ोस के घर मीराबाई चानू टीवी देखने गई, तो वहां जंगल से उसके गठ्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। उसकी मां बोली, ''बेटी आज यदि हमारे पास बैल गाड़ी होती तो तूझे गठ्ठर उठाकर न लाना पड़ता।''

''बैलगाड़ी कितने रूपए की आती है माँ ?'' मीराबाई ने पूछा

''इतने पैसों की जितने हम कभी जिंदगीभर देख न पाएंगे।''

''मगर क्यों नहीं देख पाएंगे, क्या पैसा कमाया नहीं जा सकता? कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी खरीदने के लिए पैसा कमाने का?'' चानू ने पूछा तो तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, ''तू तो लड़कों से भी अधिक वजन उठा लेती है, यदि वजन उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन जरूर भारी – भारी वजन उठाकर खेल में सोना जीतकर उस मैडल को बेचकर बैलग़ाड़ी खरीद सकती है।''

''अच्छी बात है मैं सोना जीतकर उसे बेचकर बैलगाड़ी खरीदूंगी।'' उसमें आत्मविश्वास था।

उसने वजन उठाने वाले खेल के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन उसके गांव में वेटलिटिंफ्ग सेंटर नहीं था, इसलिए उसने रोज़ ट्रेन से 60 किलोमीटर का सफर तय करने की सोची।

शुरुआत उन्होंने इंफाल के खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की।

एक दिन जाने मे वह लेट हो गयी.. रात का समय हो गया। शहर में उसका कोई ठिकाना न था, कोई उसे जानता भी न था। उसने सोचा कि किसी मन्दिर में शरण ले लेगी और कल अभ्यास करके फिर अगले दिन शाम को गांव चली जाएगी।

एक अधूरा निर्माण हुआ भवन उसने देखा जिस पर आर्य समाज मन्दिर लिखा हुआ था। वह उसमें चली गई। वहां उसे एक पुरोहित मिला, जिसे उसने बाबा कहकर पुकारा और रात को शरण मांगी।

''बेटी मैं आपको शरण नहीं दे सकता, यह मन्दिर है और यहां एक ही कमरे पर छत है, जिसमें मैं सोता हूँ । दूसरे कमरे पर छत अभी डली नहीं, एंगल पड़ गई हैं, पत्थर की सिल्लियां आई पड़ी हैं लेकिन पैसे खत्म हो गए। तुम कहीं और शरण ले लो।''

''मैं रात में कहाँ जाउँगी बाबा,'' मीराबाई आगे बोली, ''मुझे बिन छत के कमरे में ही रहने की इजाजत दे दो।''

''अच्छी बात है, जैसी तेरी मर्जी।'' बाबा ने कहा।

वह उस कमरे में माटी एकसार करके उसके उपर ही सो गई, अभी कमरे में फर्श तो डला नही था। जब छत नही थी तो फर्श कहां से होता भला। लेकिन रात के समय बूंदाबांदी शुरू हो गई और उसकी आंख खुल गई।

मीराबाई ने छत की ओर देखा। दीवारों पर उपर लोहे की एंगल लगी हुई थी, लेकिन सिल्लियां तो नीचे थी। आधा अधूरा जीना भी बना हुआ था। उसने नीचे से पत्थर की सिल्लिया उठाई और उपर एंगल पर जाकर रख दी और फिर थोड़ी ही देर में दर्जनों सिल्लियां कक्ष की दीवारों के उपर लगी एंगल पर रखते हुए कमरे को छाप दिया।

उसके बाद वहां एक बरसाती पन्नी पड़ी थी वह सिल्लियों पर डालकर नीचे से फावड़ा और तसला उठाकर मिटी भर – भरकर उपर छत पर सिल्लियो पर डाल दी। इस प्रकार मीराबाई ने छत तैयार कर दी।

बारिश तेज हो गई, और वह अपने कमरे में आ गई। अब उसे भीगने का डर न था, क्योंकि उसने उस कमरे की छत खुद ही बना डाली थी।

अगले दिन बाबा को जब सुबह पता चला कि मीराबाई ने कमरे की छत डाल दी तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने उसे मन्दिर में हमेशा के लिए शरण दे दी, ताकि वह खेल की तैयारी वहीं रहकर कर सके, क्योंकि वहाँ से खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निकट था।

बाबा उसके लिए खुद चावल तैयार करके खिलाते और मीराबाई ने कक्षों को गाय के गोबर और पीली माटी से लिपकर सुन्दर बना दिया था।

समय मिलने पर बाबा उसे एक किताब थमा देते, जिसे वह पढ़कर सुनाया करती और उस किताब से उसके अन्दर धर्म के प्रति आस्था तो जागी ही साथ ही देशभक्ति भी जाग उठी।

इसके बाद मीराबाई चानू 11 साल की उम्र में अंडर – 15 चैंपियन बन गई और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।

लोहे की बार खरीदना परिवार के लिए भारी था। मानसिक रूप से परेशान हो उठी मीराबाई ने यह समस्या बाबा से बताई, तो बाबा बोले, ''बेटी चिंता न करो, शाम तक आओगी तो बार तैयार मिलेगा।''

वह शाम तक आई तो बाबा ने बांस की बार बनाकर तैयार कर दी, ताकि वह अभ्यास कर सके।

बाबा ने उनकी भेंट कुंजुरानी से करवाई। उन दिनों मणिपुर की महिला वेटलिफ़्टर कुंजुरानी देवी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी।

इसके बाद तो मीराबाई ने कुंजुरानी को अपना आदर्श मान लिया और कुंजुरानी ने बाबा के आग्रह पर इसकी हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठाया।

जिस कुंजुरानी को देखकर मीरा के मन में विश्व चैंपियन बनने का सपना जागा था, अपनी उसी आइडल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकार्ड को मीरा ने 2016 में तोड़ा, वह भी 192 किलोग्राम वज़न उठाकर।

2017 में विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप, अनाहाइम, कैलीफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में उसे भाग लेने का अवसर मिला।

मुकाबले से पहले एक सहभोज में उसे भाग लेना पड़ा। सहभोज में अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे।

राष्ट्रपति ने देखा कि मीराबाई को उसके सामने ही पुराने बर्तनों में चावल परोसा गया, जबकि सब होटल के शानदार बर्तनों में शाही भोजन का लुत्फ ले रहे थे।

राष्ट्रपति ने प्रश्न किया, ''इस खिलाड़ी को पुराने बर्तनों में चावल क्यों परोसा गया, क्या हमारा देश इतना गरीब है कि एक लड़की के लिए बर्तन कम पड़ गए, या फिर इससे भेदभाव किया जा रहा है, यह अछूत है क्या?''

''नहीं महामहिम ऐसी बात नहीं है,'' उसे खाना परोस रहे लोगों से जवाब मिला, '' इसका नाम मीराबाई है। यह जिस भी देश में जाती है, वहाँ अपने देश भारत के चावल ले जाती है। यह विदेश में जहाँ भी होती है, भारत के ही चावल उबालकर खाती है। यहाँ भी ये चावल खुद ही अपने कमरे से उबालकर लाई है ।''

''ऐसा क्यों ?'' राष्ट्रपति ने मीराबाई की ओर देखते हुए उससे पूछा।

''महामहिम, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने ही देश का अन्न खाती हूँ।''

''ओह् बहुत देशभक्त हो तुम, जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, भारत में जाकर उस गांव के एकबार अवश्य दर्शन करूंगा।'' राष्ट्रपति बोले।

''महामहिम इसके लिए मेरे गांव में जाने की क्या जरूरत है ?''

''क्यों ?''

''मेरा गांव मेरे साथ है, मैं उसके दर्शन यहीं करा देती हूँ।''

''अच्छा कराइए दर्शन!'' कहते हुए उस मूर्ख लड़की की बात पर हंस पड़े राष्ट्रपति।

मीराबाई अपने साथ हैंडबैग लिए हुए थी, उसने उसमें से एक पोटली खोली, फिर उसे पहले खुद माथे से लगाया फिर राष्ट्रपति की ओर करते हुए बोली, ''यह रहा मेरा पावन गांव और महान देश।''

''यह क्या है?'' राष्ट्रपति पोटली देखते हुए बोले, ''इसमें तो मिट्टी है ?''

''हाँ यह मेरे गांव की पावन मिट्टी है। इसमें मेरे देश के देशभक्तों का लहू मिला हुआ है, इसलिए यह मिट्टी नहीं, मेरा सम्पूर्ण भारत हैं...''

''ऐसी शिक्षा तुमने किस विश्वविद्यालय से पाई चानू?''

''महामहिम ऐसी शिक्षा विश्वविद्यालय में नही दी जाती, ऐसी शिक्षा तो गुरु के चरणों में मिलती है, मुझे आर्य समाज में हवन करने वाले बाबा से यह शिक्षा मिली है, मैं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर सुनाती थी, उसी से 'मुझे देशभक्ति की प्रेरणा मिली।''

''सत्यार्थ प्रकाश ?''

''हाँ सत्यार्थ प्रकाश,'' चानू ने अपने हैंडबैग से सत्यार्थ प्रकाश की प्रति निकाली और राष्ट्रपति को थमा दी, ''आप रख लीजिए मैं हवन करने वाले बाबा से और ले लूंगी।''

''कल गोल्डमैडल तुम्ही जितोगी,'' राष्ट्रपति आगे बोले, ''मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे भगवान हनुमानजी ने पहाड़ हाथों पर उठा लिया था, लेकिन कल यदि तुम्हारे मुकाबले हनुमानजी भी आ जाएं तो भी तुम ही जितोगी...तुम्हारा भगवान भी हार जाएगा, तुम्हारे सामने कल।''

राष्ट्रपति ने वह किताब एक अधिकारी को देते फिर आदेश दिया, ''इस किताब को अनुसंधान के लिए भेज दो कि इसमें क्या है, जिसे पढ़ने के बाद इस लड़की में इतनी देशभक्ति उबाल मारने लगी कि अपनी ही धरती के चावल लाकर हमारे सबसे बड़े होटल में उबालकर खाने लगी।''

चानू चावल खा चुकी थी, उसमें एक चावल कहीं लगा रह गया, तो राष्ट्रपति ने उसकी प्लेट से वह चावल का दाना उठाया और मुँह में डालकर उठकर चलते बने।

''बस मुख से यही निकला, ''यकीनन कल का गोल्ड मैडल यही लड़की जितेगी, देवभूमि का अन्न खाती है यह।''

और अगले दिन मीराबाई ने स्वर्ण पदक जीत ही लिया, लेकिन किसी को इस पर आश्चर्य नहीं था, सिवाय भारत की जनता के...

अमेरिका तो पहले ही जान चुका था कि वह जीतेगी, बीबीसी जीतने से पहले ही लीड़ खबर बना चुका था ।

जीतते ही बीबीसी पाठकों के सामने था, जबकि भारतीय मीडिया अभी तक लीड खबर आने का इंतजार कर रही थी।

इसके बाद चानू ने 196 किग्रा, जिसमे 86 किग्रा स्नैच में तथा 110 किग्रा क्लीन एण्ड जर्क में था, का वजन उठाकर भारत को 2018 राष्ट्रमण्डल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया।

इसके साथ ही उन्होंने 48 किग्रा श्रेणी का राष्ट्रमण्डल खेलों का रिकार्ड भी तोड़ दिया।

2018 राष्ट्रमण्डल खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण जीतने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 15 लाख की नकद धनराशि देने की घोषणा की।

2018 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

यह पुरस्कार मिलने पर मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और बाबा के मन्दिर को पक्का करने के लिए एक लाख रुपए उन्हें गुरु दक्षिणा में दिए।

**ऐसी संघर्षमय प्रेरक गाथा विद्यालयो मे पढ़ाई जानी चाहिए!**

साभार

# मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के गेयटी थियेटर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। आज के दिन हम अपने उन शूरवीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से कारगिल के युद्ध में विजय हासिल की। उन्होंने कहा कि 22 वर्ष पूर्व कारगिल की चोटियों पर जो विजय गाथा लिखी गई वह हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि

वर्ष 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ भारतीय सेना ने ऑप्रेशन विजय चलाया जो आठ मई से शुरू होकर 26 जुलाई, 1999 तक चला।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कारगिल में ऑप्रेशन विजय के दौरान मिली जीत इस देश के सैनिकों के अदम्य साहस और संकल्पों की जीत थी। उन्होंने कहा कि जिन वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उन्हें उनकी वीरता के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। युद्ध के दौरान देश के 527 वीर सैनिक शहीद हुए और 1300 से अधिक घायल हुए थे। हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है और प्रदेश के रणबांकुरों ने साहस और बलिदान की परम्परा को बनाए रखा है तथा भारतीय सेना में सेवा करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान 527 शहीद सैनिकों में 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश के थे और चार सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था जिनमें दो वीर सपूत हिमाचल प्रदेश के थे। कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के थे जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस युद्ध में जिला बिलासपुर के सैनिक हवलदार संजय कुमार को भी अतुलनीय शौर्य के लिए सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि अब तक राज्य को 1096 वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रदेश के 1246 वीर सपूतों ने मातृ भूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध व अन्य सैन्य ऑप्रेशनों में शहीद सैनिकों तथा अन्य कारणों से मारे गए सैनिकों के आश्रितों और अपंग हुए सैनिकों को अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। कारगिल युद्ध के दौरान प्रदेश के सभी 52 शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को पांच लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की गई है। 50 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले 12 सैनिकों को 2.5 लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान राशि तथा 50 प्रतिशत से कम अपंगता वाले छः सैनिकों के लिए एक लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान राशि दी गई है। प्रदेश के 52 शहीदों के परिवारों में से 44 परिवारों के एक-एक आश्रित को उनके रोजगार के लिए आवेदन उपरान्त रोजगार और नौ अपंग हुए सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

इसके अतिरिक्त पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा ऑप्रिशन कारगिल और विभिन्न आप्रेशनों में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए विशेष योजना के तहत पैट्रोल पम्प व गैस एजेन्सी देने का प्रावधान भी किया गया है। ऑप्रेशन में शहीद हुए प्रदेश के सैनिकों के 28 आश्रितों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के माध्यम से गैस एजेन्सी व पैट्रोल पम्प आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य सैन्य अभियानों में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को भी राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों को भी सम्मानित किया।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश ने बहुत सी लड़ाइयों का सामना किया है जिनमें भारतीय सैनिकों ने राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखण्डता बनाए रखने के लिए अपने साहस और पराक्रम का अदम्य उदाहरण प्रस्तुत किया और मातृ भूमि की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए हैं।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने इस अवसर पर देशभक्ति गीत और वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया।

सांसद सुरेश कश्यप, नगर-निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, उप-महापौर शैलेन्द्र चैहान, पूर्व सांसद विमला कश्यप, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, सक्षम गुड़िया बोर्ड की अध्यक्षा रूपा शर्मा, एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा, मुख्य सचिव अनिल खाची, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक मोहित चावला, ब्रिगेडियर आर. सिहाग, ब्रिगेडियर ए.के. शर्मा, कर्नल युद्धवीर सिंह और कर्नल विक्रम जीत सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे

# भारत को अपना 39वां विश्व धरोहर स्थल प्राप्त हुआ

**शिमला।** तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर (रामप्पा मंदिर) को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में अंकित किया गया।

अब तक की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि में, तेलंगाना राज्य में वारंगल के पास, मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर (जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है) को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में अंकित किया गया है। यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में लिया गया। रामप्पा मंदिर, 13 वीं शताब्दी के अनुपम स्थापत्य कला का प्रतीक है जिसका नाम इसके वास्तुकार, रामप्पा के नाम पर रखा गया था। इस मंदिर को सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में एकमात्र नामांकन के लिए प्रस्तावित किया गया था।

यूनेस्को ने एक ट्वीट में घोषणा करते हुए कहा, 'अभी-अभी विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित: काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर (रामप्पा मंदिर), भारत के तेलंगाना में। वाह-वाह!'

यूनेस्को द्वारा काकतीय रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से इस राजसी मंदिर परिसर की यात्रा करने और इसकी भव्यता का साक्षात अनुभव प्राप्त करने का भी आग्रह किया।

यूनेस्को के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा( 'अति उत्तम! सभी को बधाई, खासकर तेलंगाना के लोगों को।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'प्रतिष्ठित रामप्पा मंदिर महान काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। मैं आप सभी से इस राजसी मंदिर परिसर की यात्रा करने और इसकी भव्यता का साक्षात अनुभव प्राप्त करने का आग्रह करता हूं।'

केन्द्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना के वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, (जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है) को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद किया।

केन्द्रीय मंत्री ने इस अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की पूरी टीम को भी बधाई दी और विदेश मंत्रालय का भी धन्यवाद किया।

मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति (डब्ल्यूएचसी) की बैठक वर्ष 2020 में आयोजित नही हो सकी और 2020 व 2021 के लिए नामांकन पर वर्तमान में जारी आनलाइन बैठकों की एक श्रृंखला में चर्चा की गई है। 25 जुलाई 2021 को रामप्पा मंदिर पर चर्चा हुई।

रेड्डी ने कहा कि वर्तमान में समिति के अध्यक्ष के रूप में चीन के साथ विश्व धरोहर समिति में 21 सदस्य हैं और सफलता का श्रेय उस सद्भावना को दिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यकाल में यूनेस्को के सदस्य देशों के साथ बनाए हैं।

## रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर पर एक संक्षिप्त विवरण

**रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने कराया था। यहां के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। 40 वर्षों तक मंदिर निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार के नाम पर इसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है।**

**काकतीयों के मंदिर परिसरों की विशिष्ट शैली, तकनीक और सजावट**

**काकतीय मूर्तिकला के प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। रामप्पा मंदिर इसकी अभिव्यक्ति है और बार-बार काकतीयों की रचनात्मक प्रतिभा का प्रमाण प्रस्तुत करती है। मंदिर छह फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है, जिसमें दीवारों, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी से सजावट की गई है, जो काकतीय मूर्तिकारों के अद्वितीय कौशल को प्रमाणित करती है।**

**समयानुरूप विशिष्ट मूर्तिकला व सजावट और काकतीय साम्राज्य का एक उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य है। मंदिर परिसरों से लेकर प्रवेश द्वारों तक काकतीयों की विशिष्ट शैली, जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है, दक्षिण भारत में मंदिर और शहर के प्रवेश द्वारों में सौंदर्यशास्त्र के अत्यधिक विकसित स्वरूप की पुष्टि करती है।**

**यूरोपीय व्यापारी और यात्री मंदिर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे और ऐसे ही एक यात्री ने उल्लेख किया था कि मंदिर 'दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा' था।**

# वनों के संरक्षण में जन सहभागिता महत्वपूर्ण:विधानसभा उपाध्यक्ष

**शिमला/शैल।**विधानसभा उपाध्यक्ष डा हंसराज ने कहा कि चुराह घाटी में मौजूद अपार वन संपदा से सरकार को राजस्व प्राप्त होने के साथ स्थानीय लोगों को घर-द्वार पर आय के बेहतर विकल्प उपलब्ध हुए हैं।

उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की बेहतर वायु गुणवत्ता कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों के उपचार में अन्य राज्यों की तुलना में मददगार रही।

विधानसभा उपाध्यक्ष 72 वें मंडल स्तरीय वन महोत्सव के तहत सुखधार में आयोजित पौधारोपण अभियान में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बोल रहे थे।

डा हंसराज ने इस दौरान देवदार का पौधा रोपित कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनसाधारण में जागरूकता के लिए विशेष प्राथमिकता के साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में वनों का अधिक विस्तार है ,वहां पेयजल के स्त्रोतों की कमी नहीं।

विधानसभा उपाध्यक्ष ने स्थानीय लोगों का आहवान करते हुए कहा कि भविष्य की जरूरत के अनुरूप वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित कार्यों के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वन विस्तार के लिए कई योजनाओं को आरंभ किया गया है। इसके अलावा इस बार सभी स्थानीय निकायों और पंचायत प्रतिनिधियों को 51-51 विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी रोपित करने के लिए वितरित किए जा रहे हैं ।

डा हंसराज ने कहा कि हिमगिरी क्षेत्र के सुखधार में ट्रैकिंग हट बनाने के लिए 50 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है । विभाग को जल्द औपचारिकताएं पूर्ण करने को कहा गया है।

वन विश्राम गृह हिमगिरी में दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए उपयुक्त धनराशि को उपलब्ध करवाने का आश्वासन देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने विश्रामगृह तक सड़क बनाने के लिए दो लाख रुपयों की राशि उपलब्ध करवाने का ऐलान भी किया ।

उन्होंने कहा कि कुम्हारका गांव तक सड़क बनाने के लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा गुवाड़ी गांव को भी जल्द सड़क सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी।

इसके अलावा इस क्षेत्र में जल शुद्धि विभाग द्वारा चिन्हित स्थलों पर चार हैंडपंप भी लगाए जा रहे हैं।

वन महोत्सव के दौरान पांच हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग चार हजार के करीब देवदार, गूं और अखरोट के पौधों का भी रोपण किया गया ।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

# मोदी को हिटलर से भी ज्यादा घातक मानने वाले पूर्व एसीएस पर जयराम सरकार की मेहरबानी चर्चा में

**शिमला/शैल।** हिमाचल के अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके आई.ए.एस. अधिकारी अबय शुक्ला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को जर्मन के तानाशाह हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। पिछले ''दी वायर'' के करण थापर को दिये गये चालीस मिनट के साक्षात्कार में अबय शुक्ला ने कहा है कि In the interview to The Wire, Shukla talks about what he calls "Modi's destruction of India". He says it can be divided into three broad phases – demonetisation, 2019 and COVID-19. He says "a malevolent common thread" runs through the three phases. This is how he describes the thread:

"Subjugation of constitutional and regulatory institutions, gross misuse of enforcement and police agencies, undermining of the judiciary, politicisation of the armed forces, an overbearing arrogance and insensitivity to public opinion, ruthless crushing of dissent and false propaganda and image building on a Goebbelsian scale."

In the interview, Shukla says Modi could not have achieved his almost total dominance but for the willing participation of civil servants, military officers, the judiciary, intelligence and enforcement agencies and the media. He adds: "I blame my own service and colleagues." He says they are "silent and intimidated". They don't want to stand up.

Asked by The Wire how he compares present-day India under Narendra Modi to the India of Indira Gandhi's Emergency and how he, therefore, answers an oft-posed question, "Who was worse? Indira or Modi?", this is what Shukla said: "The damage being done now is far more fundamental and longer lasting. It's almost irreparable."

However, Shukla made a further important point. He said: "Indira Gandhi had the courage to declare the Emergency. She did so openly. Modi's is an undeclared 'emergency' and, therefore, more insidious". Finally, he said: "Indira Gandhi's Emergency affected the administrative system. Modi's, on the other hand, has affected the social fabric of society. This time the poison is seeping beyond administration into society itself."

In The Wire interview, Shukla was also sharply critical of corporate India and its failure and refusal to stand up and be counted at critical moments. He said: "A corporate entity has the same legal rights as an individual, surely it should have the same moral and social duties as an individual – to condemn immoral ideology, to abjure hate and communalism, to not incite one community against the other, to distinguish between truth and falsehood." यह साक्षात्कार उनकी किताब India-The wasted Years की रिलिज़ के अवसर पर लिया गया है।

अबय शुक्ला जब प्रदेश में कार्यरत थे तब भी बहुत सारे मामलों पर उनकी रिपोर्टें काफी तल्ख रही हैं। प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं पर उनकी रिपोर्ट में पहली बार बेबाकी से यह खुलासा आया था कि चम्बा में इन परियोजनाओं के लिये 65 कि.मी तक रावी दरिया का मार्ग ही बदल दिया गया है। लेकिन एक ओर यहां अबय शुक्ला इतने बेबाक रहे हैं वहीं पर शिमला में ही अपने घर के निर्माण के सारे नियमों को अगूंठा दिखाते हुए टीडी का लाभ लेने के दोषी हैं जो व्यक्ति वन सचिव रहा हो और फिर अवैध रूप से टीडी का लाभ ले ले तो उसको लेकर क्या धारणा बनेगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। वर्ष 2001 में शिमला के मूल कोटी में दो अधिकारियों अबय शुक्ला और दीपक सानन ने धारा 118 में सरकार से अनुमति लेकर मकान बनाये और टीडी का लाभ ले लिया। उसी समय से स्थानीय लोग इसकी शिकायत करते रहे हैं। वन विभाग को अन्ततः यह जांच करनी पड़ी और इसमें इनको दोषी पाया गया। जून 2020 में वन विभाग की रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी थी। इस रिपोर्ट में इनके खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुशंसा की गयी है। विभाग की अनुशंसा का वन मन्त्री ने भी अनुमोदन करके फाईल मुख्यमन्त्री को भेज दी थी। लेकिन इस पर आज तक अगली कारवाई नहीं हो सकी है।

अब अबय शुक्ला का साक्षात्कार और उनकी किताब आने के बाद प्रदेश के प्रशासनिक तथा राजनीतिक हल्कों में एक बार फिर यह चर्चा का विषय बन गया है। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर इस पर अब कोई कारवाई करते हैं या इन अधिकारियों परअपनी मेहरबानी बनाये रखते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी हैं।

# पूर्व डीजीपी आई डी भण्डारी हुए "आप" में शामिल

## राजनीतिक पारी की करेंगे शुरूआत

**शिमला/शैल।** प्रदेश के पूर्व डीजीपी आई डी भण्डारी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके सक्रीय राजनीति में कदम रख दिया है। भण्डारी के शामिल होने से आम आदमी पार्टी प्रदेश में कितना आगे बढ़ पाती है यह तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। वैसे आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उताकर प्रदेश की राजनीति में कदम रख दिया था। उस समय पार्टी की बागडोर कांगड़ा से भाजपा के सांसद रहे पूर्व मन्त्री डा. राजन सुशांत ने संभाली थी आज राजन सुशान्त ''आप'' छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। उस समय जिन लोगों ने ''आप से चुनाव लड़ा था उनमें से आज केवल शिमला से प्रत्याशी रहे सुभाष ही पार्टी में बने हुए हैं। शायद उनके पास अधिकारिक तौर पर कोई पद भी नहीं है। अभी पार्टी ने नगर निगमों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में भाग लिया था। पार्टी के ही सूत्रों के मुताबिक शायद एक दो लोग ही पचास या इससे अधिक वोट ले पाये हैं। सात वर्षों में पार्टी अपना जनाधार क्यों नहीं बना पायी है। शायद अब तक चार लोग पार्टी की प्रधानगी कर चुके हैं। पार्टी अपना आधार क्यों नहीं बना पायी और क्यों इतनी बार प्रधान बदलने पड़े। इस सवाल पर शायद अब तक कोई मन्थन नहीं हो पाया है। यह स्पष्ट है कि पार्टी अभी तक अपनी विश्वसनीयता नहीं बना पायी है।

प्रदेश में अब तक दो ही पार्टीयों के हाथ में सत्ता रही है। सपा, बसपा भी यहां पर प्रयास कर चुकी हैं। टीएमसी ने भी प्रयास किया है। हिबिंका और हिलोपा तो कुछ चुनावी सफलता भी हासिल कर चुकी थी लेकिन फिर भी अपने को कायम नहीं रख पायी गयी है। इन पार्टीयों की विडम्बना यह रही है कि यह कभी भी भाजपा की नीतियों के खिलाफ खड़ी नहीं हो पायी है। इनके निशाने पर हमेशा कांग्रेस ही रही है। इससे यह संदेश जाता रहा है कि शायद भाजपा की ही प्रायोजित ईकाईयां रही हैं। केवल हिबिंका कांग्रेस की पृष्ठभूमि से

है। आज भी हिमाचल स्वाभिमान पार्टी, हिमाचल जन क्रान्ति पार्टी और अपना हिमाचल अपनी पार्टी प्रदेश में गठित है। लेकिन कोई भी कांग्रेस – भाजपा का विकल्प बनने की उम्मीद जनता में नहीं जगा पाया है। ऐसा क्यों हुआ है यदि इसके कारण की पड़ताल की जाये तो यह सामने आता है कि हिबिंका को छोड़कर शेष सभी पार्टीयां एक समय भाजपा में रह चुके लोगों द्वारा ही खड़ी की निकले लोगों द्वारा गठित थी इसीलिये 1998 में सत्ता की कूंजी उसके हाथ आयी थी। उस समय यदि हिबिंका – भाजपा के साथ सत्ता में भागीदारी न करती तो शायद आज प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही होता।

इस समय ''आप'' में भी जो लोग सक्रियता दिखा रहे हैं उनमें अधिकांश की पहली निष्ठा भाजपा है। बल्कि कुछ हल्कों में तो इसे भाजपा की ही प्रायोजित ईकाई माना जाता है। क्योंकि दोनों दलों भाजपा और ''आप'' को 2014 में सत्ता अन्ना के आन्दोलन के प्रतिफल के रूप में मिली थी। अन्ना का आन्दोलन एकदम संघ– भाजपा का प्रायोजित प्रयोग था यह अब सबको स्पष्ट हो चुका है। ऐसे में जब तक ''आप'' इस प्रतिछाया से बाहर नहीं आ पाती है तब तक उसकी कांग्रेस – भाजपा का विकल्प बनने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। फिर जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बहुत कुछ दिल्ली की जनता के एक बड़े हिस्सों को मुफ्त दे रखा है वैसा ही दिल्ली से बाहर भी उससे अपेक्षा की जाती है। जबकि अन्य प्रदेशों में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हर प्रदेश कर्ज में डुबा हुआ है केवल दिल्ली ही एक ऐसा प्रदेश है जिसका बजट उसकी राजस्व आय के बराबर है और दिल्ली सरकार पर कोई बड़ा कर्ज नहीं है। जबकि हिमाचल में तो कर्ज का ब्याज चुकाने के लिये भी कर्ज लिया जाता है। एसे में आज ''आप'' द्वारा प्रदेश के हर मृतक फौजी को एक – एक करोड़ की राशी देने की घोषणा करना प्रदेश का कर्जभार और बढ़ाने की दिशा में पहला कदम माना जायेगा। ''आप'' की इस घोषणा का व्यवहारिक रूप से क्या असर पड़ता है यह आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।

क्योंकि यह घोषणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति का कोई आकलन और उसपर व्यापक चर्चा किये बिना किया गया है।